



2026:AHC-LKO:41226-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 5708 / 2026

सूरज सिंह और अन्य

.... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, सचिव, गृह विभाग, सिविल सचिवालय,

लखनऊ के माध्यम से और अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : यदुवंश मणि सिंह, अजीत कुमार मिश्र

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 2

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. यह याचिका उत्प्रेषण प्रकृति की जैसी रिट जारी करने की मांग के साथ दाखिल की गई है ताकि दिनांक 27.05.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट/वाद अपराध संख्या 0093/2026 को अभिखण्डित किया जा सके। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 85, 115(2), 352 और 351(3) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धाराओं 3/4 के अंतर्गत भीटी पुलिस स्टेशन, जिला अंबेडकर नगर में दर्ज की गई थी।

2. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता क सुन। हैं और विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री को देखा है। याचिकाकर्ता भारतीय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों का लाभ पाने का हकदार है, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के समान हैं।

3. राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि कथित अपराधों के लिए सात वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 जिसमें धारा 35(3) से 35(6) तक शामिल हैं, के अंतर्गत बताए गए ढंग और प्रक्रिया का पालन करेगी। ऐसी स्थिति में, जांच अधिकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेगा।

4. यह बताना उचित होगा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-ए जैसे ही प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) 8 एससीसी 273** वाद में निम्नलिखित टिप्पणी की थी।

5. हमने राज्य के विद्वान अधिवक्ता के पक्ष पर विचार किया है। अर्नेश कुमार (उपर्युक्त) के वाद में निम्नलिखित (प्रासंगिक भाग) कहा गया था:-

"9. एक और प्रावधान, अर्थात् दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए, जिसका उद्देश्य अभियुक्त की अनावश्यक गिरफ्तारी या गिरफ्तारी के डर को रोकना है, उसे प्रभावी बनाने की आवश्यक है। दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (अधिनियम 5/2009) की धारा 6 के अंतर्गत जोड़ी गई धारा 41ए, जो इस मामले में प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

"41ए पुलिस अधिकारी के सामने पेश होने का नोटिस -

(1) पुलिस अधिकारी उन सभी मामलों में, जहाँ धारा 41 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा जिसके विरुद्ध कोई उचित शिकायत की गई है, या विश्वसनीय जानकारी मिली है, या उचित संदेह है कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है; उसे अपने सामने या नोटिस में बताई गई किसी अन्य स्थान पर पेश होने का निर्देश देगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(2) जब किसी व्यक्ति को ऐसा नोटिस जारी किया जाता है, तो उस व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह नोटिस की शर्तों का पालन करे।

(3) यदि ऐसा व्यक्ति नोटिस का पालन करता है और पालन करता रहता है, तो उसे नोटिस में बताए गए अपराध के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि पुलिस अधिकारी लिखित कारणों के आधार पर यह न माने कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

(4) यदि ऐसा व्यक्ति किसी भी समय नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या अपनी पहचान बताने से इनकार करता है, तो पुलिस अधिकारी, इस संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अधीन, उसे नोटिस में बताए गए अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकता है।"

"उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि उन सभी वादों में, जहाँ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1) के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, पुलिस अधिकारी को अभियुक्त को एक निर्धारित स्थान और समय पर अपने सामने पेश होने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी करना होगा। विधि ऐसे अभियुक्त को पुलिस अधिकारी के सामने पेश होने के लिए बाध्य करता है और यह भी कहता है कि यदि ऐसा अभियुक्त नोटिस की शर्तों का पालन करता है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहाँ पुलिस अधिकारी लिखित कारणों के आधार पर यह मानता हो कि गिरफ्तारी आवश्यक है। इस स्तर पर भी, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अंतर्गत गिरफ्तारी के लिए आवश्यक शर्तों का पालन करना होगा और मजिस्ट्रेट द्वारा उसी तरह जाँच की जाएगी जैसा कि पहले बताया गया है।

6. उपरोक्त बातों और याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के बयान को ध्यान में रखते हुए जिसमें कहा गया है कि राज्य के विद्वान अधिवक्ता के रुख को देखते हुए इस याचिका का निस्तारण किया जा सकता है और माननीय उच्चतम न्यायालय के **अर्नेश कुमार (उपर्युक्त)** वाद जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है और जिसका संबंधित भाग भी ऊपर दिया गया है में दिए गए निर्णय की टिप्पणियों को देखते हुए, इस याचिका का निस्तारण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया जाता है। साथ ही, पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से कार्रवाई करें। इस धारा में गिरफ्तारी के लिए विधि, ढंग और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-ए के प्रावधानों के समान हैं, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अर्नेश कुमार (उपर्युक्त) वाद में समझाया था।

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

15 जून, 2026

हसीनउद्दीन/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।